नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 238
दि. 01.06.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राज्यसभा चुनाव और संगठन विस्तार पर भाजपा का मंथन प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों, विधान परिषद चुनावों और संगठनात्मक विस्तार की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में रविवार को बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों, विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों तथा पार्टी संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर व्यापक चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भाजपा के संगठनात्मक पुनर्गठन और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाली अहम बैठक के रूप में देखा जा रहा है।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य उपस्थित रहे। पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक तैयारियों पर गहन मंथन किया।

सूत्रों के अनुसार बैठक का प्रमुख एजेंडा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव तथा तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव थे। इसके अलावा महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि आगामी चुनाव केवल सदन में संख्या बल बढ़ाने का अवसर नहीं हैं, बल्कि वे आने वाले वर्षों की राजनीतिक रणनीति को भी प्रभावित करेंगे।

बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष ने विभिन्न राज्यों की राजनीतिक स्थिति, राज्यसभा सीटों के गणित, सहयोगी

दलों की भूमिका और संभावित उम्मीदवारों को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने समिति को बताया कि किन राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत है, कहां सहयोगी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी और किन सीटों पर अतिरिक्त सफलता की संभावना दिखाई दे रही है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा को उन सीटों के अतिरिक्त भी तीन से चार अतिरिक्त राज्यसभा सीटें जीतने की उम्मीद है, जिन पर वर्तमान में उसके सदस्य कार्यरत हैं और जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। यही कारण है कि पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और उम्मीदवार चयन से लेकर राजनीतिक समीकरणों तक हर पहलू पर गहन विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में राज्यों से संबंधित रिपोर्टों का अवलोकन करने के बाद सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य इकाई अपनी-अपनी राज्यसभा सीटों की स्थिति का और अधिक विस्तृत अध्ययन करे तथा जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार करे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति में स्थानीय परिस्थितियों और राजनीतिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को सौंपा गया।

बैठक में विधान परिषद चुनावों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूत्रों के अनुसार विभिन्न राज्यों में होने वाले एमएलसी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष और संबंधित प्रदेश इकाइयों को सौंप दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रदेश नेतृत्व को पर्याप्त स्वतंत्रता देना चाहता है। महाराष्ट्र की राजनीति बैठक का एक प्रमुख केंद्र रही। राज्य में भाजपा की कुल 17 विधान परिषद सीटों में से 10 से 11 सीटों पर सीधे चुनाव लड़ने की संभावना पर चर्चा हुई। शेष सीटों को महायुति के सहयोगी दलों के साथ साझा करने की रणनीति पर विचार किया गया। महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच सीटों के संतुलन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में इस विषय पर भी महत्वपूर्ण सहमति बनी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक सामान्य बैठकों से अलग थी। आमतौर पर ऐसी बैठकें लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित होती हैं, लेकिन इस बार राज्यसभा चुनावों के साथ-साथ संगठनात्मक विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। यही कारण है कि राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर विशेष उत्सुकता बनी हुई है। बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ अलग से एक और महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नितिन नबीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बी.एल. संतोष शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पार्टी संगठन की वर्तमान स्थिति, लंबित नियुक्तियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन तथा आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन जल्द ही अपनी नई संगठनात्मक टीम का गठन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में रविवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को मौजूदा टीम की अंतिम महत्वपूर्ण बैठक के रूप में भी देखा जा रहा है। भाजपा संगठन में होने वाले संभावित बदलावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उत्सुकता बनी हुई है। माना जा रहा है कि आगामी वर्षों की राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में युवा चेहरों को अधिक अवसर दिए जा सकते हैं, जबकि अनुभवी नेताओं को रणनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। भाजपा नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, मीडिया विभाग के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। बैठक का मुख्य विषय केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति होगा।

चलती ट्रेन बनी जीवन का आंगन, मध्य रेल कर्मियों की तत्परता से गूंजी नवजीवन की किलकारी

मुंबई/भुसावल। भारतीय रेल को अक्सर देश की जीवनरेखा कहा जाता है, लेकिन कई बार यह केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि जीवन बचाने और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल भी बन जाती है। ऐसा ही एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य मध्य रेल के मार्ग पर देखने को मिला, जब लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन संख्या 15945 में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच रेलवे कर्मचारियों, सहयात्रियों और कंट्रोल टीम की त्वरित कार्रवाई ने एक संभावित संकट को खुशियों में बदल दिया। चलती ट्रेन में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया और महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया।

घटना 30 मई 2026 की है। ट्रेन भुसावल और इटारसी के बीच अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी, तभी शाम करीब 5:25 बजे एक यात्री रवि चौधरी घबराए हुए ट्रेन स्टाफ के पास पहुंचे। उन्होंने ट्रेन कंडक्टर एस.पी. फिरके और टिकट परीक्षक अंबरीश कुमार तिवारी को बताया कि उनकी पत्नी

ज्योति को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और उनकी स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है। चलती ट्रेन में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण स्थिति बेहद संवेदनशील थी।

मामले की गंभीरता को समझते हुए रेलवे कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले कोच बी-6 की गैलरी को अस्थायी प्रसूति कक्ष में बदलने का निर्णय लिया गया। कंबलों, चादरों और उपलब्ध संसाधनों की सहायता से एक सुरक्षित और स्वच्छ स्थान तैयार किया गया, ताकि महिला को आवश्यक सुविधा और गोपनीयता मिल सके। स्टाफ ने महिला को आरामदायक स्थिति में पहुंचाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी।

उधर, रेलवे कंट्रोल सिस्टम को भी तुरंत सक्रिय कर दिया गया। शाम 5:28 बजे ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने भोपाल कंट्रोल कार्यालय को पूरी जानकारी दी और हरदा स्टेशन पर डॉक्टर, चिकित्सा टीम तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। कंट्रोल कार्यालय ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए और हरदा स्टेशन को अलर्ट कर दिया।

इस बीच ट्रेन में मौजूद महिला यात्रियों ने भी मानवता और सहयोग की अद्भुत मिसाल पेश की। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर गर्भवती महिला की सहायता की और उसे मानसिक संबल प्रदान किया। सभी के संयुक्त प्रयासों के बीच लगभग शाम 5:40 बजे महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही नवजात की पहली किलकारी कोच में गूंजी, वहां मौजूद यात्रियों के चेहरों पर राहत और खुशी की चमक दिखाई देने लगी। कुछ देर पहले जहां चिंता और तनाव का माहौल था, वहीं अब नवजीवन के आगमन की खुशी छा गई। नवजात के जन्म के बाद भी रेलवे कर्मचारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभाले रखा। मां और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार उनकी निगरानी की जाती रही। ट्रेन अपनी निर्धारित गति से हरदा स्टेशन की ओर बढ़ती रही, जहां पहले से ही रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन प्रशासन, महिला पुलिसकर्मी और चिकित्सा दल पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे।

शाम 6:07 बजे ट्रेन हरदा स्टेशन पहुंची। वहां चिकित्सा विशेषज्ञों ने मां और नवजात की प्राथमिक जांच की। चूंकि उस समय तक नवजात की नाल नहीं काटी गई थी, इसलिए दोनों को तुरंत बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल भेजा गया। एम्बुलेंस की मदद से मां और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आगे की चिकित्सा प्रक्रिया पूरी की। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल में जांच के बाद मां और नवजात दोनों की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और संतोषजनक पाई गई। चिकित्सकों ने बताया कि समय पर मिली सहायता और उचित देखभाल के कारण किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं हुई।

टोयोटा किर्लोस्कर और गुजरात सरकार की साझेदारी से शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा, लाखों लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

मुंबई। औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Toyota Kirloskar Motor ने गुजरात सरकार के साथ एक व्यापक समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाकर सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करना है। कंपनी और राज्य सरकार के बीच हुए इस सहयोग को गुजरात के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। समझौते के तहत शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण, तकनीकी प्रशिक्षण और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं का लक्ष्य केवल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं, विद्यार्थियों और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। समझौता समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah, गुजरात के मुख्यमंत्री Bhupendra Patel, किर्लोस्कर समूह की चेयरपर्सन

एवं प्रबंध निदेशक Geetanjali Vikram Kirloskar तथा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड एवं एक्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट Vikram Gulati सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी के माध्यम से सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य में सामुदायिक पुस्तकालयों का विकास है। योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और आम नागरिकों को अध्ययन एवं ज्ञानवर्धन के बेहतर अवसर मिलेंगे। इन पुस्तकालयों में एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था, सौर ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति और आधुनिक अध्ययन संसाधनों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुमान है कि इस परियोजना से तीन लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी एक अभिनव पहल शुरू की गई है। सूरत के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कंप्यूटर एजुकेशन इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। यह बस चलती-फिरती डिजिटल कक्षा के रूप में कार्य करेगी और उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा की सुविधाएं सीमित हैं। पांच ब्लॉकों में संचालित होने वाली यह पहल लगभग 8,000 विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। वर्तमान समय में जब डिजिटल दक्षता रोजगार और शिक्षा दोनों के लिए आवश्यक बन चुकी है, तब इस प्रकार की पहल ग्रामीण छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जामनगर के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम (टी-टीईपी) लागू किया गया है। यह कार्यक्रम उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तकनीकी कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। इसके तहत मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, पेंटर और अन्य तकनीकी क्षेत्रों सहित कुल 29 ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना से लगभग 3,700 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय से युवाओं की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस साझेदारी का व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। योजना के तहत राजकोट और आसपास के क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है। ऐसे में चिकित्सा उपकरणों और बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता से स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूरस्थ शहरों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी।

ममता की बैठक में कम रही विधायकों की मौजूदगी, बंगाल की राजनीति में तेज हुई अटकलें

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण विधायक बैठक में अपेक्षा से बहुत कम विधायकों की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पार्टी नेतृत्व जहां इसे परिस्थितिजन्य और संगठनात्मक व्यस्तताओं का परिणाम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती असहजता और नेतृत्व के प्रति घटते विश्वास का संकेत बताने में जुट गया है। रविवार शाम ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। यह बैठक ऐसे समय आयोजित की गई थी जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी तथा वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी नेतृत्व इन घटनाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए राज्यव्यापी विरोध कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है।

हालांकि बैठक शुरू होने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 80 विधायकों वाले दल में से केवल करीब 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे। इनमें अधिकांश वरिष्ठ और पुराने नेता शामिल थे। विधायकों की कम उपस्थिति ने तुरंत राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया और विपक्ष ने इसे पार्टी के भीतर असंतोष से जोड़ना शुरू कर दिया।

बैठक स्थल के बाहर मीडिया की मौजूदगी और लगातार उठते सवालों के बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कुणाल घोष को स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि बैठक में कम

उपस्थिति का पार्टी के भीतर किसी प्रकार के मतभेद या असंतोष से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार बड़ी संख्या में विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी द्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रमों में व्यस्त थे, जिसके कारण वे कालीघाट नहीं पहुंच सके। कुणाल घोष ने बताया कि हाल ही में पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाले गए हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, जिनकी रिहाई और कानूनी सहायता की व्यवस्था में स्थानीय विधायक सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। इसी कारण अनेक विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से संपर्क कर बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था।

उनके अनुसार बैठक को औपचारिक रूप से आगे के लिए टाल दिया गया और जो विधायक पहले से पहुंच चुके थे, उन्होंने आपसी चर्चा कर संगठनात्मक विषयों पर विचार-विमर्श किया। तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि बैठक में कम उपस्थिति को किसी राजनीतिक संदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि किसी राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण बैठक में उसके अधिकांश विधायक उपस्थित नहीं होते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि यह तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती असहजता और बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत हो सकता है।

मानिकतला से भाजपा विधायक तापस रॉय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का अनुपस्थित रहना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। उन्होंने इसे ममता बनर्जी के नेतृत्व के प्रति घटते विश्वास का संकेत बताते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि तृणमूल नेताओं ने विपक्ष के इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बैठक में कम उपस्थिति के पीछे कई व्यावहारिक कारण भी हो सकते हैं। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार उग्र होती जा रही है और विभिन्न दलों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे माहौल में स्थानीय स्तर पर विधायकों की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी द्वारा राज्यव्यापी विरोध कार्यक्रमों की घोषणा भी की जा चुकी है, जिसके चलते कई विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने आगामी दिनों के लिए व्यापक राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा की है। पार्टी नेतृत्व के अनुसार एक जून को राज्यभर में वार्ड स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक विरोध मार्च निकाले जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पार्टी नेताओं पर हुए हमलों के खिलाफ जनमत तैयार करना और कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश देना है। इसके बाद दो जून को ममता बनर्जी स्वयं कोलकाता में एक दिवसीय धरने का नेतृत्व करेंगी। इस धरने में अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले, वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा, कोलकाता के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तथा अन्य राजनीतिक मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से वह अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट रखने में सफल होगी।

हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। राज्य की सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद पार्टी अब बदलते राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रही है। विपक्ष लगातार उसे घेरने का प्रयास कर रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत बनाए रखने और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी एक बैठक में कम उपस्थिति को सीधे राजनीतिक संकट का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। हालांकि यह भी सच है कि बड़े राजनीतिक दलों में प्रतीकात्मक घटनाओं का महत्व काफी होता है और विपक्ष ऐसे अवसरों का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। आने वाले दिनों में यदि तृणमूल कांग्रेस अपने विरोध कार्यक्रमों में बड़ी भागीदारी दिखाने में सफल रहती है तो वर्तमान विवाद स्वतः शांत हो सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बैठक को लेकर चर्चा जारी है। एक पक्ष इसे सामान्य संगठनात्मक परिस्थिति बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहा है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

मेहनत हारती है, जुगाड़ जीतता है

हमारे देश में दो चीजें कभी खत्म नहीं होतीं—एक उम्मीद और दूसरी जांच। हर साल लाखों युवा उम्मीद लेकर परीक्षाओं में बैठते हैं और हर बड़े पेपर लीक के बाद जांच शुरू हो जाती है। उम्मीद और जांच दोनों समानांतर चलती रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उम्मीद युवाओं की होती है और जांच व्यवस्था की। बीच में जो सबसे ज्यादा परेशान होता है, वह वही छात्र होता है जिसने सचमुच पढ़ाई की होती है।

पेपर लीक अब कोई साधारण घटना नहीं रह गई है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है, जिसकी चर्चा गांव की चौपाल से लेकर संसद तक होती है। पहले परीक्षा का मतलब था मेहनत, तैयारी और प्रतिस्पर्धा। अब परीक्षा का मतलब है—पहले तैयारी करो, फिर परीक्षा दो, फिर परिणाम का इंतजार करो और उसके बाद यह भी इंतजार करो कि कहीं पेपर लीक की खबर तो नहीं आने वाली। विद्यार्थी अब परीक्षा केंद्र से कम और समाचार चैनलों से ज्यादा डरने लगे हैं।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेपर लीक की दुनिया में हर व्यक्ति निर्दोष होता है। पकड़े जाने पर कोई यह नहीं कहता कि उसने पेपर लीक कराया है। हर कोई किसी और की ओर इशारा करता है। कोई एजेंसी को दोष देता है, कोई अधिकारियों को, कोई कर्मचारियों को और कोई राजनीतिक साजिश का हवाला देता है। ऐसा लगता है जैसे पेपर अपने आप ही लीक हो गया हो और किसी को पता ही न हो कि यह महान कार्य किसने किया। आज पेपर लीक एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति बन चुका है, जिसका कोई निश्चित चेहरा नहीं है। यह कभी किसी कोचिंग सेंटर के आसपास दिखाई देता है, कभी किसी परीक्षा केंद्र के पास, कभी किसी साइबर कैफे में और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के घर में, जिसका शिक्षा से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होता। जांच एजेंसियां भी हैरान रहती हैं कि आखिर पेपर का सफर प्रश्नपत्र निर्माण केंद्र से शुरू होकर इतनी दूर-दूर तक कैसे पहुंच जाता है। पेपर लीक की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लोकतांत्रिक भावना है। यह किसी एक राज्य, भाषा, जाति या क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करता। जहां परीक्षा होगी, वहां इसकी संभावना भी मौजूद रहेगी। यह राष्ट्रीय एकता का शायद सबसे विचित्र उदाहरण है। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं, लेकिन उनकी समस्याएं आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती हैं। कभी-कभी तो लगता है कि कुछ लोग परीक्षा को ज्ञान की नहीं, बल्कि नेटवर्किंग की प्रतियोगिता समझ बैठे हैं। एक छात्र किताबें पढ़ता है, दूसरा नोट्स बनाता है और तीसरा संपर्क बनाता है। अंत में सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होती है जिसके संपर्क सबसे मजबूत निकलते हैं। यह अलग बात है कि बाद में जांच होने पर वही संपर्क अचानक पहचानने से इंकार कर देते हैं। पेपर लीक के बाद नेताओं की सक्रियता भी देखने लायक होती है। सत्ता पक्ष कहता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष कहता है कि सरकार दोषियों को बचा रही है। दोनों पक्षों के बयान इतने नियमित होते हैं कि कभी-कभी लगता है कि वे भी परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। केवल विद्यार्थी ही ऐसा वर्ग है जिसे न बयान से राहत मिलती है और न जांच समिति की घोषणा से। इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद दृश्य वह होता है जब कोई परीक्षा रद्द होती है। हजारों-लाखों छात्र महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं। कई लोग दूर-दराज के गांवों से शहरों तक पहुंचते हैं। परिवार पैसे खर्च करते हैं, उम्मीदें बांधते हैं। फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। उस क्षण किसी छात्र की निराशा का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। लेकिन व्यवस्था अक्सर इसे केवल एक प्रशासनिक निर्णय मानकर आगे बढ़ जाती है। पेपर लीक का कारोबार भी समय के साथ आधुनिक हो गया है। पहले जमाने में लोग प्रश्नपत्र की फोटोकॉपी तलाशते थे, अब डिजिटल युग में स्क्रीनशॉट, चैट, क्लाउड और एन्क्रिप्टेड संदेशों की चर्चा होती है। तकनीक का उपयोग शिक्षा सुधार के लिए कम और पेपर लीक की कहानियों में अधिक सुनाई देने लगा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तकनीकी नवाचार को गलत दिशा में मोड़ दिया है। विडंबना यह है कि जिन परीक्षाओं का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों का चयन करना होता है, वही परीक्षाएं कई बार व्यवस्था की कमजोरियों का प्रदर्शन बन जाती हैं।

कर्नाटक में बदलाव के बाद की चुनौतियां

सिद्दरमैया के त्यागपत्र के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर राज्य में गुटबाजी और समस्याओं का सामना करना होगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के त्यागपत्र देने के साथ ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राज्य की कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। इससे शिवकुमार की तो चाहत पूरी हो गई, लेकिन यह कहना कठिन है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ सामान्य होने जा रहा है या फिर राज्य की विभिन्न समस्याओं के समाधान की राह आसान हो गई है। सिद्दरमैया ने त्यागपत्र देने की घोषणा करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जैसा कहा, मैंने वैसा किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा आकर कांग्रेस की केंद्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होने का आग्रह ठुकराते हुए कहा कि वे राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे।

चूंकि सिद्दरमैया जमीनी स्तर की राजनीति करने वाले नेता हैं और उनका अपना जनाधार है, इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे शिवकुमार के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसके नतीजे में वहां नए सिरे से गुटबाजी भी पनप सकती है, क्योंकि शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल से सिद्दरमैया के कुछ समर्थक बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक ही है कि शिवकुमार अपने हिसाब से शासन से चलाएंगे और इसके लिए वे प्रशासन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को किनारे कर सकते हैं। इसके आसार कम ही हैं कि सिद्दरमैया अपने उत्तराधिकारी शिवकुमार के लिए खुला मैदान छोड़ेंगे, क्योंकि जमीनी राजनीति करने वाला कोई नेता अपना राजनीतिक वर्चस्व इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपने देश में तो ऐसा और भी कम होता है। अपने यहां उम्रदराज नेता तब तक राजनीति से रिटायर ही नहीं होते, जब तक उन्हें बिल्कुल किनारे न कर दिया जाए। कांग्रेस सिद्दरमैया की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती।

शिवकुमार 2023 में तभी से मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठता के आधार पर सिद्दरमैया का चयन किया। शिवकुमार का दावा था कि उनके और सिद्दरमैया के बीच इसे लेकर सहमति कायम हुई थी कि दोनों ढाई-ढाई वर्ष तक सत्ता संभालेंगे। अपने इस दावे के अनुरूप वे पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पद हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सिद्दरमैया पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में वे तीन वर्ष बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हुए। स्पष्ट है कि उन्होंने मजबूरी में पद छोड़ा।

कर्नाटक की तरह एक समय राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी इसे लेकर खींचतना हुई थी कि दोनों के बाच ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने की सहमति बनी थी। सचिन पायलट ने बहुत कोशिश की कि इस कथित सहमति के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों को भी ठुकरा दिया। इस कारण सचिन पायलट एवं उनके बीच खींचतान जारी रही और कांग्रेस आलाकमान अंत समय तक कोई फैसला नहीं कर सका। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ।

यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव के बीच इसे लेकर झगड़ा होता रहा कि ढाई-ढाई साल तक सत्ता संभालने की बात हुई थी। यहां भी कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय का एक कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान भी बनी। कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधानसभा चुनाव के करीब एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए बाध्य किया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को मिली। इसके चलते गुटबाजी को बढ़ावा मिला और विधानसभा चुनावों में इसका लाभ आम आदमी पार्टी ने उठाया।

कर्नाटक में दो वर्ष बाद चुनाव होने हैं। कहना कठिन है कि तब क्या होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि कर्नाटक में 1980 के बाद कोई भी सरकार सत्ता में नहीं लौटी है। शिवकुमार इस सिलसिले को तोड़ सकेंगे, यह कहना इसलिए कठिन है, क्योंकि कर्नाटक कई समस्याओं से घिरा है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आइटी सिटी के रूप में विख्यात है, लेकिन इस समय बेंगलुरु के साथ देश भर का आइटी उद्योग समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक में बेंगलुरु को छोड़कर एक दो शहर ही सही तरह विकसित हो पाए हैं। बेंगलुरु और शेष राज्य में जो आर्थिक असमानता दिखती है, वह यही बताती है कि सरकारों ने अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक उसी तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे अन्य कई राज्य।

किसी भी दल के लिए कर्नाटक के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना इसलिए कठिन होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को संतुष्टि के नाम पर विकास के काम कम, लोकलुभावन योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवड़ी राजनीति कर्नाटक के लिए एक समस्या बन गई है। लोकलुभावन योजनाएं पूरी करने के फेर में राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। ऐसी योजनाओं से एक तो मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपती है और दूसरे राज्य की वित्तीय सेहत बिगड़ती है।

ऐसा कुछ अन्य राज्यों में भी हो रहा है। कर्नाटक की तरह कई राज्यों में आर्थिक विकास राजधानी और चुनिंदा शहरों में ही केंद्रित दिखता है। अधिकांश राज्यों के पिछड़ेपन का कारण यही है कि वहां की सरकारें प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान नहीं देतीं। इससे आर्थिक असंतुलन और असमानता बढ़ती है। यह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। यह स्थिति शिवकुमार के लिए चुनौती बन सकती है।

प्रमुख राज्यों में देखा जाए तो कांग्रेस के पास तेलंगाना को छोड़कर कर्नाटक ही बचा है। यदि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से राज्य की सत्ता निकल गई और भाजपा सत्ता में आ गई तो उसका देशव्यापी प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस के लिए उसका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। स्पष्ट है कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तो तय हो गया, लेकिन उनके लिए राज्य को समस्याओं से उबार पाना आसान नहीं होने वाला।

प्रेरणा

संबंधों, संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ का जीवंत दस्तावेज

पंजाबी कथा-साहित्य की समृद्ध परंपरा में डॉ. करमजीत सिंह नडाला एक ऐसे कथाकार हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन के अनेक जटिल पक्षों को बड़ी संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। उनका नवीन कहानी-संग्रह 'ग्लेशियर पिघल गया' इस बात का प्रमाण है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और मनुष्य के अंतर्मन को समझने का सशक्त उपकरण भी है। यह संग्रह पाठक को मानवीय संबंधों, सामाजिक विसंगतियों, आर्थिक विषमताओं और जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराता है। संग्रह में शामिल छह लंबी कहानियां अपने कथ्य, शिल्प और भावबोध के कारण विशेष महत्व रखती हैं।

मूल रूप से पंजाबी भाषा में प्रकाशित इस संग्रह का हिन्दी रूपान्तरण लेखिका एवं अधिवक्ता नीलम नारंग ने किया है। अनुवाद की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने मूल रचनाओं की आत्मा को सुरक्षित रखा है। कहानियों में पंजाब की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोकजीवन की सहजता, भाषा की मिठास और पात्रों की स्वाभाविकता पूरी तरह बनी हुई है। अनुवाद पढ़ते समय कहीं भी कृत्रिमता का अनुभव नहीं होता। बल्कि ऐसा लगता है कि कहानियां सीधे हिन्दी में ही रची गई हों। यह उपलब्धि किसी भी अनुवादक के लिए विशेष महत्व रखती है।

संग्रह की सभी कहानियां अलग-अलग विषयों पर केंद्रित होते हुए भी एक साझा सूत्र से जुड़ी हैं और वह है मनुष्य के जीवन में संबंधों की भूमिका। डॉ. नडाला के पात्र केवल कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज में मौजूद वास्तविक लोग हैं। उनकी खुशियां, दुख, संघर्ष, असफलताएं और आकांक्षाएं पाठक को अपने जीवन के अनुभवों की याद दिलाती हैं। यही कारण है कि कहानियां पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। 'ऐसे ठीक नहीं रूपा' संग्रह की आरंभिक कहानी है, जो आर्थिक असमानता और उससे उत्पन्न मानसिक तनाव को केंद्र में रखती है। कहानी की नायिका रूपा अपने जीवन के लिए ऐसे सपने देखती है जो उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। वह वैभव, आराम और प्रतिष्ठा से भरे जीवन की कल्पना करती है, लेकिन उसका विवाह एक साधारण मिस्त्री से हो जाता है। यहीं से उसके भीतर असंतोष की प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे-धीरे यह असंतोष उसे ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो उसके जीवन को संकट में डाल देते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता, तब उसका जीवन किस प्रकार भटकाव का शिकार हो सकता है। संग्रह की शीर्षक कहानी 'ग्लेशियर पिघल गया' स्त्री-पुरुष संबंधों की जटिलता को एक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। यहां ग्लेशियर केवल बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि उन नैतिक और भावनात्मक सीमाओं का प्रतीक है जो मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाए रखती हैं। जब ये सीमाएं टूटती हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार और सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है। लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से यह दिखाया है कि भावनात्मक कमजोरियां और सामाजिक दबाव किस प्रकार जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कहानी का प्रभाव पाठक के मन में लंबे समय तक बना रहता है।

'वनवास' कहानी आधुनिक समाज में धन और संपत्ति के बढ़ते प्रभाव को केंद्र में रखती है। आज के समय में रिश्तों की जगह आर्थिक हितों ने ले ली है। परिवारों में बढ़ते विवादों का एक बड़ा कारण जायदाद और संपत्ति भी है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि लालच और स्वार्थ किस प्रकार मनुष्य को अपने ही लोगों से दूर कर देते हैं। कहानी का कथानक हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि संबंधों में प्रेम और विश्वास समाप्त हो जाएं तो भौतिक समृद्धि भी जीवन को सुखी नहीं बना सकती। संग्रह की सबसे प्रभावशाली कहानियों में 'अंदर का महाभारत' का विशेष स्थान है। यह कहानी कई स्तरों पर एक साथ चलती है। इसमें प्रेम की विफलता की पीड़ा है, सामाजिक परिस्थितियों का दबाव है और इतिहास की त्रासदी भी है। लेखक ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की पृष्ठभूमि को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि उस पूरे दौर की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। हरदीप का चरित्र कहानी में प्रेम, समर्पण और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण कहानी भावनात्मक और वैचारिक दोनों स्तरों पर पाठक को प्रभावित करती है।

'लम्बी पतझड़' जीवन के उन क्षणों की कहानी है, जब व्यक्ति अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार ने मनुष्य को सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन उससे आत्मीयता और संबंधों की गर्माहट भी छीन ली है। लेखक ने इस कहानी में अकेलेपन, स्मृतियों और समय के प्रभाव को बहुत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। कहानी यह संदेश देती है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि उन भावनात्मक रिश्तों का भी नाम है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं।

'मरीज' इस संग्रह की सबसे गंभीर और विचारोत्तेजक कहानियों में से एक है। पहली दृष्टि में यह कहानी बीमारी और उपचार की लगती है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि लेखक यहां मनुष्य और समाज की मानसिक अवस्थाओं की पड़ताल कर रहा है। कहानी यह प्रश्न उठाती है कि वास्तविक बीमारी क्या है—शरीर की या मन की? कई बार मनुष्य बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। संबंधों में आई दरारें, अकेलापन, असुरक्षा और सामाजिक दबाव उसे धीरे-धीरे खोखला कर देते हैं। यही इस कहानी का मूल संदेश है। डॉ. करमजीत सिंह नडाला की लेखन शैली अत्यंत सहज, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है। वे बिना किसी अनावश्यक जटिलता के गहरे विषयों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण इतना स्वाभाविक है कि वे वास्तविक जीवन के लोग प्रतीत होते हैं। संवादों में जीवन की सच्चाई झलकती है और घटनाओं में विश्वसनीयता दिखाई देती है। यही कारण है कि उनकी कहानियां केवल पढ़ी नहीं जातीं, बल्कि महसूस की जाती हैं।

पंजाब त्रिस्तरीय निकाय चुनाव के दलगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सियासी मायने अहम

पंजाब के त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत- सिर्फ स्थानीय सत्ता का संघर्ष नहीं हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का "सेमीफाइनल" माने जा रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक चुनाव नहीं हैं, बल्कि ये पंजाब की बदलती क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय दलों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संघीय लोकतांत्रिक छवि से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि 2026 के इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा "पॉलिटिकल टेस्ट" माना जा रहा है। पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 के चुनाव आयोग और मतगणना से जुड़े अब तक के मुख्य आंकड़े निम्नलिखित हैं- कुल 102 शहरी निकायों- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों- में चुनाव हुए, जहां मतदान प्रतिशत लगभग 63.94% दर्ज किया गया। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 76.18% मतदान हुआ। नगर निगम क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 59.91% मतदान दर्ज हुआ। नगर परिषदों में लगभग 65.06% मतदान हुआ। कुल 1,896 वार्डों के लिए मतदान कराया गया। लगभग 7,555 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 79 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।

इस चुनाव में अब तक आए नतीजों और घोषित रुझानों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। आप ने लगभग 886 वार्ड जीते। जबकि कांग्रेस ने लगभग 358 वार्ड जीते। वहीं शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 191–192 वार्ड, भाजपा को 172 वार्ड, बसपा को 7 वार्ड, और निर्दलीय उम्मीदवारों को 251 वार्ड पर जीत मिली। वहीं सीट प्रतिशत के हिसाब से मोटे अनुमान के मुताबिक, आप ने लगभग 50% के आसपास वार्ड, कांग्रेस ने लगभग 20% वार्ड, एसएडी ने लगभग 9% वार्ड, बीजेपी ने लगभग 7% वार्ड और बीएसपी सहित अन्य ने लगभग 14% सीटो पर जीत व बढ़त हासिल की है।

जहाँ तक वोट प्रतिशत का सवाल है, तो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और संकलित रुझानों के अनुसार दल और अनुमानित वोट प्रतिशत इसप्रकार हैं- आम आदमी पार्टी को लगभग 41–44%, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 24–27%, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 13–16%, शिरोमणि अकाली दल को लगभग 10–13% और निर्दलीय व अन्य लगभग 5–8% वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार आप का वोट शेयर सबसे अधिक रहा, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर, शिरोमणि अकाली दल तीसरे नम्बर पर रही और इसने ग्रामीण-सिख बेल्ट में कुछ आधार वापस पाया, जबकि बीजेपी चौथे स्थान पर जाकर कुछ शहरी पॉकेट्स तक सीमित रही। आधिकारिक वोट प्रतिशत का सबसे विश्वसनीय डेटा sec.punjab.gov.in पर उपलब्ध है।

अब जिस तरह से इन चुनावों के नतीजे आए हैं, उसने यह तय कर दिया है कि राज्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत हो रही है और कांग्रेस, भाजपा, एसएडी जैसे विपक्षी दल बचाव की मुद्रा में आ चुके हैं। लिहाजा पंजाब त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव के दलगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सियासी मायने अहम हैं।

पहला, आप (AAP) अपने जनविश्वास की परीक्षा में सफलः मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव सत्ता में आने के बाद शहरी जनसमर्थन मापने का अवसर था, जो बड़ी जीत के साथ उम्मीदों पर खरा उतरा। निकायों में मजबूत जीत मिली है। इससे यह संदेश गया कि पंजाब में आप सिर्फ "वैकल्पिक प्रयोग" नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। आप की बड़ी जीत इसी ओर संकेत करती है। आप (AAP) के लिए ये चुनाव सबसे अहम थे क्योंकि वह राज्य की सत्ता में है। नगर निकायों में मजबूत प्रदर्शन से यह संदेश गया कि जनता अभी भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर भरोसा कर रही है। इसमें आप के लिए फायदे की बात यह है कि शहरी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत होने से "दिल्ली मॉडल" की तरह "पंजाब मॉडल" को भी प्रचारित करने का अवसर मिला। साथ ही विपक्ष के बिखराव का भी लाभ मिला। वहीं, आप के लिए खतरे की बात यह है कि नशा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दखल के आरोप बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

दूसरा, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई पर विपक्षी हैसियत बनाईः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पंजाब आखिरी बड़े राज्यों में से एक है जहाँ वह अब भी राजनीतिक पुनर्जीवन की उम्मीद देखती है। वह मिली भी और पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत पा गई। भले ही कांग्रेस ने निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन किया, लेकिन इतनी सीट मिल गई कि उसका संगठनात्मक संकट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पंजाब कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, लेकिन लगातार संगठनात्मक कमजोरी और गुटबाजी ने उसे कमजोर किया है। फिर भी कांग्रेस के लिए अवसर यह है कि कई शहरों में दूसरे स्थान पर भी उसने मजबूत उपस्थिति दिखाई है, और वह खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर चुकी है, जबकि आगे शहरी असंतोष को भुनाने का मौका मिलेगा।

तीसरा, अकाली दल के पुनर्जीवन का संघर्ष बढ़ाः शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन और पुराने सत्ता-विरोधी माहौल के बाद अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन चुनावों ने बता दिया कि "पंजाबियत" और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति अभी कितनी प्रभावी है। शिरोमणि अकाली दल के लिए ये चुनाव "राजनीतिक पुनर्जीवन" की परीक्षा थे और आगे भी रहेंगे। किसान आंदोलन और पुराने भ्रष्टाचार आरोपों के बाद पार्टी जो कमजोर हुई थी, वह स्थिति नहीं बदली है।

लिहाजा अब वह खुद को "पंजाबियत" और क्षेत्रीय अस्मिता की पार्टी के रूप में फिर स्थापित करना चाहती है। शिरोमणि अकाली दल के लिए सकारात्मक संकेत यह है कि ग्रामीण-सिख वोट बैंक में आंशिक वापसी हुई, जो भाजपा से अलग होकर स्वतंत्र पहचान मजबूत करने की कोशिश हो सकती है, जबकि उसकी चुनौती यह है कि शहरी क्षेत्रों में कमजोर संगठन के चलते युवा मतदाताओं के बीच सीमित आकर्षण है।

अभियान

भोजन केवल आहार नहीं, संस्कृति है : कढ़ाई में भोजन करने की मनाही और उससे जुड़ी मान्यताओं का रहस्य

भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि उसे जीवन, स्वास्थ्य, धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा गया है। सनातन परंपरा में अन्न को ब्रह्म कहा गया है और भोजन को देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों, पुराणों और लोकपरंपराओं में भोजन से जुड़े अनेक नियम और मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं। इन नियमों का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था को बनाए रखना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है।

भारतीय घरों में बचपन से ही सिखाया जाता है कि भोजन हमेशा थाली, कटोरी या उचित पात्र में बैठकर करना चाहिए। रसोई में जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है, उसी में सीधे भोजन करना उचित नहीं माना जाता। विशेष रूप से कढ़ाई, भगोने या पतीले में सीधे भोजन करने को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आधुनिक जीवनशैली और भागदौड़ के कारण आज कई लोग सुविधा के लिए कढ़ाई या पैन से ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे अच्छा नहीं माना गया है। इसके पीछे केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं।

धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अन्न को देवत्व का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां देवी अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास होता है। भोजन बनाने वाला पात्र केवल एक बर्तन नहीं होता, बल्कि वह उस प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिसमें कच्चा अन्न पककर जीवनदायी भोजन का रूप लेता है। इसलिए उसे विशेष सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति उसी बर्तन में सीधे भोजन करता है, जिसमें भोजन तैयार किया गया हो, तो यह अन्न के प्रति असम्मान का संकेत माना जाता है। लोकविश्वास के अनुसार इससे माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न हो सकती हैं और घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है।

भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी का संबंध केवल धन से नहीं, बल्कि अन्न, समृद्धि और संतोष से भी है। जिस घर में भोजन का आदर किया जाता है, वहां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके विपरीत भोजन की बर्बादी, अनादर या असावधानी को अशुभ माना गया है। कढ़ाई में सीधे भोजन करने को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। यद्यपि यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसके पीछे जीवन को अनुशासित और व्यवस्थित बनाने का संदेश भी निहित है।

लोकपरंपराओं में एक रोचक मान्यता यह भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति कढ़ाई में भोजन करता है, उसके विवाह के समय वर्षा होने की संभावना रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में ऐसी मान्यताएं लोगों को व्यवहारिक अनुशासन सिखाने का माध्यम रही हैं। पुराने समय में बुजुर्ग इन प्रतीकात्मक बातों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को भोजन संबंधी मर्यादाओं का पालन करने की प्रेरणा देते थे। इन मान्यताओं का वास्तविक उद्देश्य किसी भय को पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और संस्कारों को बनाए रखना था।

यदि व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो कढ़ाई में सीधे भोजन न करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वच्छता है। भोजन पकाने वाले बर्तन का उपयोग पूरे परिवार के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसी बर्तन में सीधे भोजन कर ले, तो उसमें मौजूद शेष भोजन जूठा माना जाएगा। भारतीय संस्कृति में जूठे और शुद्ध भोजन के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है। विशेष रूप से संयुक्त परिवारों में यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक ही बर्तन से कई लोगों के लिए भोजन परोसा जाता था। इसलिए भोजन को पहले अलग थाली में निकालने की परंपरा विकसित हुई।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह नियम पूरी तरह तर्कसंगत प्रतीत होता है। कई बार कढ़ाई या पतीला भोजन पकाने के बाद लंबे समय तक गर्म रहता है। यदि कोई व्यक्ति सीधे उसी बर्तन से भोजन करता है, तो उसके हाथ या मुंह के जलने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा धातु के अत्यधिक गर्म बर्तनों में भोजन करने से असुविधा भी हो सकती है। इसलिए भोजन को पहले उचित पात्र में निकालकर थोड़ा ठंडा होने देना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है।

भारतीय परंपरा में भोजन करने की प्रक्रिया को भी एक प्रकार की साधना माना गया है। भोजन से पहले हाथ-पैर धोना, ईश्वर का स्मरण करना, शांत मन से बैठकर भोजन करना और अन्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जब भोजन को थाली में परोसकर ग्रहण किया जाता है, तब व्यक्ति उसे अधिक सम्मान और ध्यान के साथ खाता है। इसके विपरीत सीधे कढ़ाई या पैन से भोजन करना जल्दबाजी और असावधानी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग सदैव भोजन को उचित पात्र में ग्रहण करने की सलाह देते रहे हैं।

वास्तुशास्त्र में भी रसोई और भोजन को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि भोजन बनाते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दिशा का प्रभाव भोजन की ऊर्जा पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार रसोई में खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा मानी जाती है और यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। इस दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

इसके विपरीत दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाने को कम शुभ माना गया है। लोकमान्यता है कि इससे घर में तनाव और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वास्तुशास्त्र इन्हें ऊर्जा संतुलन और मानसिक प्रभावों के आधार पर देखता है। भारतीय समाज में इन नियमों का पालन लंबे समय से किया जाता रहा है और अनेक परिवार आज भी इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं।

भोजन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण परंपरा स्नान के बाद भोजन तैयार करने और ग्रहण करने की है। शास्त्रों में शारीरिक और मानसिक शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। माना जाता है कि स्नान करने के बाद व्यक्ति अधिक पवित्र अवस्था में होता है और उसी अवस्था में भोजन बनाना तथा ग्रहण करना श्रेष्ठ माना जाता है। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित है।

भारतीय संस्कृति में गाय को विशेष सम्मान प्राप्त है। इसलिए सुबह की पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की भावना का भी परिचायक है। माना जाता है कि गाय को पहली रोटी अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी प्रकार अंतिम रोटी कुत्ते या अन्य जीवों के लिए निकालने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में प्रचलित है। इससे मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश मिलता है। आज के आधुनिक युग में कई लोग इन परंपराओं को केवल रूढ़ियां मानकर अनदेखा कर देते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि समय के साथ कुछ मान्यताओं की व्याख्या बदल सकती है, लेकिन उनके मूल उद्देश्य को समझना आवश्यक है। कढ़ाई में सीधे भोजन न करने की परंपरा के पीछे स्वच्छता, सुरक्षा, अनुशासन और अन्न के प्रति सम्मान जैसी महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। यदि हम इन मूल भावनाओं को समझें, तो पाएंगे कि ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे।

भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और जीवनशैली को भी प्रभावित करता है। इसलिए भोजन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा संदेश अवश्य निहित होता है। कढ़ाई में भोजन न करने की मान्यता भी ऐसी ही एक परंपरा है, जो हमें अन्न का सम्मान करना, स्वच्छता बनाए रखना और जीवन में अनुशासन का पालन करना सिखाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने भोजन को पूजा के समान महत्व दिया और उससे जुड़े नियमों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज भी यदि हम इन परंपराओं के सार को समझकर अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी, बल्कि हमारा जीवन भी अधिक संतुलित, स्वस्थ और सुखमय बन सकेगा।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

डिजिटल युग की सबसे बड़ी जनगणना की शुरुआत: सूरत में 12 हजार से अधिक कर्मी जुटेंगे, हर घर तक पहुंचेगी 'जनगणना-2027'

देश की विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण और भविष्य की नीतियों की आधारशिला मानी जाने वाली जनगणना की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। 'जनकल्याण के लिए जनगणना' के संकल्प के साथ भारत की 16वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 8वीं जनगणना का पहला चरण 1 जून 2026 से गुजरात सहित पूरे देश में प्रारंभ हो रहा है। सूरत शहर और जिले में भी इस महाअभियान को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेष बात यह है कि यह देश के इतिहास की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन स्व-गणना जैसी सुविधाओं का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

वर्ष 2011 के बाद पहली बार होने जा रही इस जनगणना को देश के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनसंख्या, आवास, सामाजिक संरचना, शिक्षा, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी एकत्र कर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाओं को आकार देगी। इसी कारण इसे केवल एक सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य की योजना निर्माण का आधार माना जाता है।

सूरत, जो देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले महानगरों में शामिल है, इस जनगणना अभियान में विशेष महत्व रखता है। बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और लगातार बढ़ते प्रवासी समुदाय के कारण यहां सटीक आंकड़ों का संकलन अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। प्रशासन ने इस विशाल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शहर और जिले को विशेष हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (एचएलबी) में विभाजित किया है, ताकि प्रत्येक घर और प्रत्येक परिवार तक व्यवस्थित रूप से पहुंचा जा सके।

जनगणना निदेशक सुजल जे. मयात्रा ने नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा है कि जनगणना केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने से ही सरकार को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।

सूरत महानगर क्षेत्र में जनगणना के पहले चरण के लिए व्यापक मानव संसाधन तैनात किया गया है। शहर में कुल 10,800 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं और प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक गणनाकर्मी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्य की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 1,800 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,737

हाउस लिस्टिंग ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं, जहां 2,646 गणनाकर्मी और 441 सुपरवाइजर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस प्रकार सूरत शहर और जिले में कुल मिलाकर 15 हजार से अधिक अधिकारी, गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे।

इतने बड़े स्तर पर कार्य को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने प्रशिक्षण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया है। सभी गणनाकर्मियों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को तीन चरणों में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल एप्लिकेशन के उपयोग, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया, नागरिकों से संवाद, गोपनीयता के नियमों और तकनीकी समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन के कारण इस बार डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और त्रुटिरहित होगा।

इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल स्वरूप है। पहली बार कागजी फॉर्मों की जगह मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर विशेष एप विकसित किए गए हैं, जो गुजराती सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इन एप्लिकेशनों में ऑफलाइन डेटा संग्रहण की सुविधा भी दी गई है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने की स्थिति में भी गणनाकर्मी अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकेंगे। बाद में नेटवर्क उपलब्ध होने पर डेटा सुरक्षित रूप से केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। डिजिटल जनगणना के साथ-साथ नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसे सेल्फ-एन्यूमेरेशन कहा गया है। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सूरत जिले में इस सुविधा को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया है। प्रशासन के अनुसार अब तक 37 हजार से अधिक नागरिकों ने डिजिटल माध्यम से स्वयं गणना के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से 32 हजार से अधिक लोगों ने अपनी प्रक्रिया पूरी भी कर ली है, जबकि लगभग 5 हजार आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि डिजिटल सेवाओं को लेकर नागरिकों में जागरूकता और स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

1 जून से 30 जून 2026 तक चलने वाले पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउस काउंट ऑपरेशन (एचएलओ) किया जाएगा। इस दौरान गणनाकर्मी प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और आवास संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेंगे। इसमें मकान की स्थिति, निर्माण का प्रकार, परिवार के सदस्यों की संख्या, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, बिजली, रसोई गैस, संचार साधन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न शामिल होंगे। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार को देश में मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का व्यापक आकलन प्राप्त होगा। प्रशासन का मानना है कि इन आंकड़ों के माध्यम से आवास योजनाओं, स्वच्छता कार्यक्रमों, पेयजल परियोजनाओं, शहरी विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। विशेष रूप से तेजी से बढ़ते शहरों में बुनियादी सुविधाओं की मांग का सटीक अनुमान लगाने में यह जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा। यह चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान जनसंख्या गणना के साथ-साथ देशव्यापी जाति गणना भी की जाएगी। लंबे समय से चर्चा का विषय रही जातिगत आंकड़ों की गणना को इस बार जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है, जिसके कारण इस चरण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इससे देश की सामाजिक संरचना और विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति का विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा।

जनगणना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को लेकर भी रहती है। इस संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम-1948 तथा जनगणना नियम-1990 के तहत एकत्र की जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। किसी भी नागरिक द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग कर निर्धारण, कानूनी कार्रवाई, पुलिस जांच अथवा किसी अन्य प्रशासनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। कानून के अनुसार जनगणना में प्राप्त आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है।

हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। जानबूझकर गलत जानकारी देना या जानकारी देने से इनकार करना कानून के तहत दंडनीय माना गया है। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे गणनाकर्मियों का सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

सूरत में शुरू होने जा रही यह डिजिटल जनगणना केवल आंकड़े जुटाने का अभियान नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में विकास की दिशा तय करने वाला राष्ट्रीय उपक्रम है। शहर की बढ़ती आबादी, बदलती सामाजिक संरचना और तेज आर्थिक विकास के बीच यह जनगणना भविष्य की नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगी। प्रशासन को उम्मीद है कि नागरिकों के सहयोग से यह महाअभियान सफलतापूर्वक पूरा होगा और देश को अधिक सटीक, आधुनिक तथा विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त होंगे।

हिमाचल की खाई में समा गई खुशियों की यात्रा, छत्तीसगढ़ के दो परिवारों समेत आठ लोगों के बचने की उम्मीद क्षीण

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध साच पास मार्ग पर पर्यटकों से भरी एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद उसमें सवार आठ लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना का शिकार हुए लोगों में छत्तीसगढ़ के दो परिवारों के सात सदस्य और एक स्थानीय चालक शामिल हैं। राहत और बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन वाहन की स्थिति और दुर्घटना स्थल की भयावह परिस्थितियों को देखते हुए किसी के जीवित बचने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है।

यह हादसा उस समय हुआ जब छत्तीसगढ़ से आए पर्यटक हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए चंबा और डलहौजी क्षेत्र की यात्रा पर निकले थे। परिवारों ने छुट्टियां बिताने और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने की योजना बनाई थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हो सकती है।

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के दो परिवार डलहौजी घूमने पहुंचे थे। वे पिछले कुछ दिनों से वहां ठहरे हुए थे और 29 मई को प्रसिद्ध साच पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। साच पास हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम और रोमांचक पर्वतीय मार्गों में गिना जाता है। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र अपने बर्फीले पहाड़ों, घुमावदार सड़कों और मनमोहक दृश्यों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि यह मार्ग अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जोखिमपूर्ण यात्रा के लिए भी जाना जाता है।

बताया जाता है कि पर्यटक दिनभर की यात्रा के बाद देर शाम तक होटल वापस नहीं लौटे। जब रात काफी हो गई और उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया, तब होटल प्रबंधन को चिंता हुई। कई बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर होटल संचालकों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया।

रातभर और अगले दिन सुबह तक चले खोज अभियान के दौरान राहत टीमों ने बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग के विभिन्न हिस्सों की जांच की। अंततः एक गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त एर्टिगा कार दिखाई दी। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए थे और उसका अधिकांश हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था।

पुलिस के अनुसार वाहन में अरविंद, उनकी पत्नी प्राची, उनके दो बेटे दर्श और अपशद, पी. जी. कार्तिगहेयन, उनकी पत्नी मणिमाला, उनका पुत्र नंदन तथा स्थानीय चालक विश्वास सवार थे। ये सभी लोग एक साथ पर्यटन के उद्देश्य से हिमाचल आए थे। हादसे के बाद से सभी लापता बताए जा रहे हैं और बचाव दल लगातार उनकी तलाश में जुटा हुआ है।

चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना स्थल अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। खाई की गहराई, पहाड़ी ढलानों की खतरनाक स्थिति और लगातार बदलते मौसम के कारण राहत एवं बचाव कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर बचाव दल को रस्सियों और विशेष उपकरणों की सहायता से नीचे उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन की जो स्थिति सामने आई है, उसे देखकर यह आशंका और गहरी हो गई है कि दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा होगा।

बचाव अभियान में पुलिस, स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता ली जा रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद टीमें लगातार मौके पर डटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता। इस घटना की खबर जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंची, वहां प्रभावित परिवारों और परिचितों के बीच चिंता और शोक का माहौल फैल गया। परिजन लगातार प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं और हर नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। परिवारों को अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों के बयान और वाहन की स्थिति ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। हालांकि पर्वतीय मार्गों पर यात्रा हमेशा जोखिम से भरी रहती है। विशेषकर साच पास जैसे दुर्गम इलाकों में मौसम, संकरी सड़कें, तीखे मोड़ और गहरी खाइयां दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ा देती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी और अनुभवी चालकों की आवश्यकता होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चंबा जिले में इसी महीने पर्यटकों से जुड़ा यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 10 मई को भटियात क्षेत्र में गुजरात के पर्यटकों से भरी एक इनोवा कार गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संवेदनशील मार्गों पर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा बैरियर और निगरानी व्यवस्था बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। हालांकि प्राकृतिक परिस्थितियों और कठिन भौगोलिक संरचना के कारण जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है।

फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें राहत एवं बचाव अभियान पर टिकी हुई हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों के संपर्क में है। इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि पहाड़ों की खूबसूरती जितनी आकर्षक होती है, उनकी चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर होती हैं। छत्तीसगढ़ से खुशी और उत्साह के साथ निकले दो परिवारों की यह यात्रा अब एक ऐसी त्रासदी में बदल गई है, जिसने कई जिंदगियों को गहरे दुख और अनिश्चितता में डाल दिया है। जब तक अंतिम पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक उम्मीद की एक किरण बनी हुई है, लेकिन दुर्घटना की भयावहता को देखते हुए पूरा देश उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिनकी खुशियां हिमाचल की एक गहरी खाई में कहीं खो गई हैं।

वराछा में बाल मजदूरी पर बड़ा प्रहार, संयुक्त अभियान में 14 बच्चे मुक्त; संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

सूरत में बाल मजदूरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। शहर के वराछा क्षेत्र स्थित मुक्तिधाम सोसाइटी में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने विशेष जांच अभियान चलाकर 14 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया। इनमें बाल मजदूर, किशोर श्रमिक और किशोरियां शामिल हैं, जो विभिन्न इकाइयों में लंबे समय तक काम करने को मजबूर थे। कार्रवाई के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि संबंधित संचालकों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सूरत जिला टास्क फोर्स द्वारा चलाया गया यह अभियान 30 मई को आयोजित किया गया। बाल मजदूरी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाए गए इस विशेष अभियान में श्रम विभाग, सूरत महानगरपालिका, फैक्ट्री निरीक्षण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), शी-टीम तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के कारण अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया गया।

जांच के दौरान टीमों ने मुक्तिधाम सोसाइटी क्षेत्र में संचालित हॉट फिक्सिंग कार्य से जुड़ी इकाइयों, कार्यस्थलों और आवासीय परिसरों की विस्तृत तलाशी ली। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नाबालिग और किशोर श्रमिक काम करते हुए पाए गए। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 14 बच्चों को वहां से मुक्त कराया। इनमें 6 किशोर लड़के, 4 बाल मजदूर और 4 किशोरियां शामिल थीं।

प्राथमिक जांच में सामने आया कि मुक्त कराए गए अधिकांश बच्चे राजस्थान और बिहार के विभिन्न जिलों से संबंधित हैं। बच्चों की उम्र लगभग 10 से 17 वर्ष के बीच पाई गई, जबकि किशोरियों की आयु 14 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार ये बच्चे पिछले एक से दो महीनों से संबंधित इकाइयों में कार्यरत थे और उन्हें प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक काम कराया जाता था। दिनभर की मेहनत के बीच उन्हें केवल एक घंटे का विश्राम दिया जाता था। इसके बदले उन्हें प्रतिमाह 5,000 से 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता था।

अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि किसी भी बच्चे के पास आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इससे उनकी वास्तविक उम्र और रोजगार की परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों की अनुपस्थिति बाल श्रम और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में जांच को और महत्वपूर्ण बना देती है। इसी कारण सभी बच्चों को तत्काल कार्यस्थल से हटाकर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार मुक्त कराए गए लड़कों को कतारगाम स्थित वी.आर. पोपावाला चिल्ड्रन्स होम में रखा गया है, जबकि लड़कियों को रांदेर स्थित चिल्ड्रन्स होम फॉर गर्ल्स में सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया है। यहां बच्चों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, परामर्श और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उनके परिवारों, शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी एकत्र की जा रही है।

जिला बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की आयु, पहचान और अन्य तथ्यों की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि बच्चों को किस परिस्थिति में काम पर लगाया गया था और इसके पीछे कौन-कौन जिम्मेदार हैं। जांच पूरी होने के बाद संबंधित मालिकों, संचालकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि बाल मजदूरी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। कम उम्र में बच्चों को श्रम में झोंकने से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे मामलों में प्रशासन की नीति शून्य सहिष्णुता की है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

सूरत जैसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक शहर में विभिन्न राज्यों से रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व और संचालक नाबालिग बच्चों को काम पर लगाने का प्रयास करते हैं। प्रशासन का मानना है कि बाल मजदूरी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केवल छापेमारी ही नहीं, बल्कि जनजागरूकता, निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी आवश्यक है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं बाल मजदूरी, बाल तस्करी या बच्चों के शोषण से संबंधित कोई मामला दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या संबंधित अधिकारियों को दें। प्रशासन का कहना है कि समाज की सक्रिय भागीदारी से ही बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त किया जा सकता है।

वराछा में हुई यह कार्रवाई न केवल 14 बच्चों को श्रम के चक्र से बाहर निकालने में सफल रही है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि बाल मजदूरी के खिलाफ प्रशासन की मुहिम लगातार जारी है। आने वाले दिनों में भी ऐसे विशेष अभियान चलाकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के प्रयास जारी रहेंगे।

सूर्या हत्याकांड में बड़ा मोड़: 50 हजार का इनामी असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर, इलाके में फैली सनसनी

गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में रविवार सुबह उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब हत्या के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। खोड़ा कॉलोनी में 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की निर्मम हत्या के बाद से फरार चल रहा असद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। कई दिनों से उसकी तलाश में जुटी पुलिस को रविवार सुबह महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसके आधार पर घेराबंदी की गई। मुठभेड़ के दौरान असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली असद को लगी और बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

इस घटनाक्रम के बाद पूरे गाजियाबाद में हत्याकांड को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी के मारे जाने से मामले की जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी, हालांकि अभी भी कई अन्य आरोपितों की तलाश जारी है और पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार 28 मई को खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार निवासी 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। बताया गया था कि सूर्या पर उसके परिचित असद और उसके साथियों ने किसी विवाद के दौरान हमला किया था। हमले में सूर्या गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था और परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था।

हत्या के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी असद लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। लगातार दबिश और निगरानी के बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बचता रहा, जिससे जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई थी।

रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए एक स्थान पर पहुंचने वाला है और वहां से क्षेत्र छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दी। जब पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर गोली चला दी। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। अधिकारियों के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा और कानून के तहत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें असद गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल अवस्था में असद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका उपयोग किन-किन घटनाओं में किया गया था।

सूर्या चौहान हत्याकांड ने पिछले कुछ दिनों में पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। मृतक के परिजनों ने लगातार आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त सजा दी जानी चाहिए। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद परिजनों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वे पूरे मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ के बाद भी जांच समाप्त नहीं हुई है। मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। जिन आरोपितों को पहले गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या की साजिश किस तरह रची गई और इसमें किन-किन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही।

तेजपुर में सनसनीखेज हमला: विवाहिता पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार, खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंची; आरोपी फरार

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सदर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव में एक सिरफिरे युवक ने दिनदहाड़े एक विवाहिता पर धारदार ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले से गांव में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों को उसके शरीर पर आए गहरे घावों पर लगभग 25 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजपुर गांव निवासी रेखा, पत्नी राकेश, अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं। इसी दौरान गांव का रहने वाला युवक सुजल अचानक वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के महिला पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी के हाथ में धारदार ब्लेड था, जिससे उसने महिला के शरीर पर लगातार कई वार किए। हमला इतना अचानक और तेज था कि महिला को संभलने का अवसर तक नहीं मिला।

हमले के दौरान महिला के गले, कमर और पैरों पर गंभीर चोटें आईं। ब्लेड के वार से शरीर के कई हिस्सों से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। कुछ ही क्षणों में महिला खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। घायल महिला को तत्काल निजी वाहन की सहायता से महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों की टीम ने तुरंत उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर पर कई गहरे घाव पाए गए, जिन पर करीब 25 टांके लगाने पड़े। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार महिला को लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि अगले कुछ दिन उसके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचा ली गई, लेकिन चोटों की गंभीरता को देखते हुए अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है।

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी युवक हमले के बाद तुरंत फरार हो गया था। पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों की भी जांच की जा रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी ने महिला पर हमला क्यों किया। पुलिस पारिवारिक, व्यक्तिगत और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी और पीड़िता के बीच किसी प्रकार का पूर्व परिचय या विवाद रहा हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

दिनदहाड़े हुई इस घटना ने तेजपुर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह खुलेआम किसी महिला पर हमला होना बेहद चिंताजनक है। घटना के बाद गांव में लोगों के बीच आरोपी के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दिन के समय सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की वारदात हो सकती है तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

चोरवाड के कृषि मजदूर की बेटी काजल वाजा ने एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता

▸▸ स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए काजल ने इस वर्ष कक्षा-12 की परीक्षा में ड्रॉप लेकर तनतोड़ मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई

▸▸ काजल ने हांगकांग में आयोजित स्पर्धा में 4X100 मीटर रिले में भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने में दिया महत्वपूर्ण योगदान

▸▸ उप मुख्यमंत्री व खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी ने काजल तथा भारतीय रिले टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभिनंदन दिया

गांधीनगर : गुजरात की उभरती स्प्रिंटर काजल वाजा ने फिर एक बार सिद्ध किया है कि दृढ़निश्चय, अनुशासन एवं अथक परिश्रम से साधारण परिवार से आने वाली प्रतिभाएँ भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जूनागढ जिले के चोरवाड गाँव की 19 वर्षीय काजल ने हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रविवार को महिलाओं की 4X100 मीटर रिले स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तमिलनाडु की भावना, हरियाणा की आरती तथा उत्तर प्रदेश की निपम के साथ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए काजल ने टीम को 45.04 सेकंड का समय दर्ज करवाने में मदद की। इस प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम ने रजत पदक जीता और अंडर-20 वर्ग में भारत ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया। भारतीय टीम ने पूर्व के 45.08 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर अपनी तेजी, टीमवर्क तथा बैटन एक्सचेंज की श्रेष्ठता प्रदर्शित की।

काजल की उपलब्धि उसकी साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में लेते हुए और प्रेरणादायी बन जाती है। उनके पिता हीराभाई वाजा जूनागढ जिले के समुद्र तटवर्ती चोरवाड गाँव के साधारण किसान हैं और कृषि मजदूरी करते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बीच भी काजल ने अपने खेल कॅरियर पर अडिग ध्यान केंद्रित रखा और अपने सपने साकार करने के लिए अनेक त्याग किए।

ट्रैक पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए काजल ने कक्षा-12 में एक वर्ष ड्रॉप लेकर प्रशिक्षण एवं स्पर्धा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी इस निष्ठा एवं मेहनत का फल उन्हें अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला है।

काजल के पारिवारिक संबंधी मंथन डाभी ने कहा, "काजल को स्कूली शिक्षाकाल से ही खेल-कूद के प्रति विशेष लगाव था और वे निरंतर विभिन्न स्पर्धाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करती आई हैं।"

काजल वाजा के कोच शिवम उपाध्याय काजल की सफलता का श्रेय उनकी अविरत मेहनत तथा श्रेष्ठता हासिल करने की तीव्र इच्छा को देते हैं।

उन्होंने कहा, "काजल देश की सबसे आशावान युवा स्प्रिंटर्स में एक हैं। उन्होंने गुजरात का गौरव बढ़ाते हुए 100 मीटर, 200 मीटर और रिले स्पर्धाओं में अनेक पदक जीते हैं। उनके अनुशासन, आत्मविश्वास तथा प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं। वे हर प्रशिक्षण सत्र में पूर्ण समर्पण के साथ भाग लेती हैं और लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं।"

हांगकांग में जीता गया रजत पदक काजल की उपलब्धियों की सूची में एक और महत्वपूर्ण योग है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2025 में राँची में आयोजित दक्षिण एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 4X100 मीटर रिले में भी रजत पदक जीता था। इसके अलावा, 60 मीटर स्पर्धा में अंडर-20 वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनके नाम है।

इस वर्ष मार्च महीने में भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम इनडोर ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में काजल ने 60 मीटर दौड़ में 7.50 सेकंड का समय दर्ज कराकर स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। इस उपलब्धि ने उन्हें भारत की सबसे प्रतिभाशाली युवा स्प्रिंटर्स में स्थान दिलाया है।

स्कूल से स्पोर्ट्स की यात्रा

काजल की खेल यात्रा गुजरात राज्य की स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात (एसएजी) के स्कूल प्रोग्राम से शुरू हुई थी। इसके बाद वे 2019 में कोडीनार स्थित जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) में जुड़ीं, जहाँ उनकी प्रतिभा को व्यवस्थित ढंग से गढ़ा गया। उनकी क्षमता को पहचान कर 2023 में उनका चयन नडियाद स्थित हाई-परफॉर्मेंस सेंटर (एचपीसी) के लिए किया गया, जहाँ वे हाल में अत्याधुनिक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी ने काजल तथा भारतीय रिले टीम को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अभिनंदन दिया।

श्री संघवी ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार खिलाड़ियों को उनके वैश्विक सपने साकार करने के लिए जरूरी सभी सुविधाएँ प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। काजल की उपलब्धि गुजरात तथा समग्र देश के लिए गौरव का क्षण है।"

उल्लेखनीय है कि इसी चैम्पियनशिप में गुजरात के अन्य एक खिलाड़ी तथा वापी निवासी राहुल जाखड़ ने डेकाथलॉन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता है।

रमशे बाळक, खीलशे बाळक : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में मेगा खिलौना कलेक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ

▸▸ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की प्रेरणा से शुरू हुए अभियान में मुख्यमंत्री सहभागी हुए

▸▸ खिलौनों के दान से बच्चों में संवेदना तथा बाँटने-साझा करने के संस्कार विकसित होते हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में रविवार को अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बोपल-घुमा स्थित आरोही ट्विन्स बंगलॉ में 'रमशे बाळक, खीलशे बाळक' (खेलेगा बच्चा, खिलेगा बच्चा) अभियान अंतर्गत मेगा खिलौना कलेक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की प्रेरणा से शुरू हुआ यह अभियान समाज के विभिन्न वर्गों को एक मानवीय कार्य के साथ जोड़ता है।

अपने बच्चों के खिलौने अन्य बच्चों के साथ बाँटने-साझा करने की भावना सामाजिक भावना, मानवता के मूल्यों तथा परिवार भावना को अधिक मजबूत बनाती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में खेल-कूद तथा खिलौने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम परिवारों के बच्चों द्वारा उपयोग में लिए गए और हाल में अनुपयोगी खिलौने जरूरतमंद बच्चों को अर्पित करने की यह पहल केवल दान का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में संवेदना, सहानुभूति एवं बाँटने-साझा करने के संस्कारों का सिंचन करने वाला अभियान है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक जुड़ने तथा अधिक से अधिक खिलौने दान करके जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के इस यज्ञ में सहभागी बनने का अनुरोध किया।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

इस कार्यक्रम में अग्रणी सर्वश्री विनोदभाई पटेल एवं दर्शनभाई पटेल, अग्रणगण्य लोग और बड़ी संख्या में नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पिछले तीन दिनों में वायरस संक्रमण से एक भी सिंह की मृत्यु दर्ज नहीं हुई, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में

▸▸ वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने गिर का दौरा किया, एशियाई सिंहों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सिंहों के संरक्षण के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध : श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

▸▸ वन मंत्री ने जामवाळा, बाबरिया तथा जसाधार केंद्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर वन विभाग एवं पशु चिकित्सकों के कामकाज की समीक्षा की

गांधीनगर : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने एशियाई सिंहों में पाए गए संक्रमण की स्थिति की ग्राउंड जीरों पर समीक्षा करने के लिए रविवार को गिर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने जामवाळा रेस्क्यू सेंटर, बाबरिया वन क्षेत्र एवं जसाधार पशु देखभाल केंद्र का दौरा कर स्थिति का निरीक्षण किया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने सम्बद्ध उच्चाधिकारियों तथा पशु चिकित्सकों की टीमों के साथ विस्तृत बैठक की और विचार-विमर्श तथा स्थिति की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि वन विभाग द्वारा समय रहते तथा प्रभावी कदम उठाए गए, जिसके कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। राहत का समाचार देते हुए उन्होंने जोड़ा कि पिछले तीन दिनों के दौरान वायरस संक्रमण के कारण एक भी सिंह की मृत्यु दर्ज नहीं हुई है।

फिर भी; किसी भी प्रकार की कोर-कसर न रहे, इसके लिए ऐहतियात एवं सतर्कता के तौर पर वन विभाग, वेटरनरी विशेषज्ञों और फील्ड स्टाफ की विशेष टीमें चौबीस घण्टे (24X7) कार्यरत हैं और सिंहों के स्वास्थ्य पर निरंतर तथा सूक्ष्मतापूर्ण नजर रख रही हैं। श्री मोढवाडिया ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात की शान समान एशियाई सिंहों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार तथा वन विभाग संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सिंहों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने गिर के वनों में गूंजने वाली सिंहों की गर्जना को आगामी पीढ़ियों तक अनावरत रखने के लिए दिन-रात देखे बिना हर स्तर पर पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे वन विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों तथा मैदान में (फील्ड पर) कार्यरत टीमों के समर्पण एवं अनावरत परिश्रम को हृदयपूर्वक सराहा।

तंबाकूमुक्त समाज की ओर सूरत का संकल्प, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिलेभर में चला व्यापक जनजागरण अभियान

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सूरत जिले में तंबाकू सेवन के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया। जिले के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन 31 मई को नवी सिविल अस्पताल के मनोरोग विभाग में किया गया, जहां स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सकों, विद्यार्थियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों की जानकारी देना ही नहीं था, बल्कि समाज को नशामुक्त और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी क्रम में सूरत जिले में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों ने भाग लेकर तंबाकूमुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

नवी सिविल अस्पताल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल बी. पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अभियान को एपिडेमिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. कौशिक मेहता की प्रेरणा और निर्देशन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तंबाकू के बढ़ते प्रभाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू सेवन केवल फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। तंबाकू के कारण कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, श्वसन संबंधी रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग भी पैसिव स्मोकिंग के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं।

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा केवल शहर तक ही सीमित न रहते हुए जिले के विभिन्न तालुका क्षेत्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण आबादी तक तंबाकू नियंत्रण का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि तंबाकू के खिलाफ प्रभावी लड़ाई तभी संभव है, जब जागरूकता अभियान समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

अभियान के अंतर्गत जनजागृति रैलियों, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA-2003) पर मार्गदर्शन सत्रों तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों, नर्सिंग विद्यार्थियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी बहनों और सामुदायिक नेताओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों और कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को इस अभियान से जोड़ना और उन्हें जागरूकता फैलाने का माध्यम बनाना था।

जागरूकता अभियान की शुरुआत उमरपाड़ा तालुका स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से की गई। यहां विद्यार्थियों को विशेष रूप से तंबाकू उद्योग द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने छात्रों को समझाया कि किस प्रकार आकर्षक विज्ञापन, सामाजिक दबाव और गलत संगति युवाओं को तंबाकू सेवन की ओर धकेल सकती है। साथ ही उन्हें पैसिव स्मोकिंग के खतरों और इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा जागरूकता रैली रही, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सिंग विद्यार्थियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तख्तियां और जागरूकता संदेश लिए प्रतिभागियों ने लोगों को तंबाकू छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। रैली के दौरान लगाए गए नारों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। "एक, दो, तीन, चार – तंबाकू और सिगरेट छोड़ो यार" तथा "तंबाकू छोड़ो, सिगरेट छोड़ो" जैसे नारों के माध्यम से समाज को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई।

कार्यक्रम में एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. परेश सुरती ने तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विश्वभर में हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन के कारण होती है। भारत में भी कैंसर और हृदय रोगों के प्रमुख कारणों में तंबाकू का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA)-2003 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार-प्रसार पर भी विभिन्न कानूनी प्रतिबंध लागू हैं।

कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी ने विशेष संदेश दिया। बच्चों ने पोस्टर, नारों और सांकेतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से "जिंदगी चुनें, तंबाकू नहीं" का संदेश दिया। उनकी प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और यह स्पष्ट किया कि तंबाकूमुक्त वातावरण केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू की लत केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। तंबाकू पर खर्च होने वाला धन परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है और कई बार गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा तथा पोषण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तंबाकू छोड़ना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के हित में उठाया गया कदम है।

कार्यक्रम के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए उपलब्ध परामर्श सेवाओं और उपचार सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में परामर्श तथा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाकर व्यक्ति इस आदत से मुक्त हो सकता है।

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम, साइकेट्री विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, तालुका एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में जिला काउंसलर कीर्तिराज सोलंकी ने सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तंबाकूमुक्त समाज का लक्ष्य तभी संभव है, जब हर व्यक्ति स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास करे।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित यह अभियान केवल एक दिवस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सतत सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है। सूरत जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया यह व्यापक जनजागरण अभियान समाज को यह संदेश देने में सफल रहा कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ विचार और नशामुक्त वातावरण ही बेहतर भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।

भावनगर रेलवे मंडल ने 24 रेलकर्मियों को दी भावपूर्ण विदाई

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित कर उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की दी शुभकामनाएँ

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर मई-2026 माह में सेवानिवृत्त हो रहे 24 रेलकर्मियों के सम्मान में दिनांक 29 मई 2026 (शुक्रवार) को रेलवे कम्युनिटी हॉल, भावनगर में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

यह समारोह वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के साथ बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

समारोह के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी फाइलें प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर रेलवे में उनके दीर्घकालीन, निष्ठापूर्ण एवं समर्पित योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यक्रम के दौरान भावुक एवं आत्मीय वातावरण में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं को स्मरण करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई। उपस्थित अधिकारियों एवं सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए गए कार्यकाल के अनुभव साझा किए तथा उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की।

अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन के नए चरण के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि रेल सेवा के दौरान अर्जित अनुभव एवं अनुशासन उनके आगामी जीवन को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत प्राप्त होने वाली धनराशि का सुविचारित एवं योजनाबद्ध उपयोग करने तथा स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने का भी संदेश दिया।

समारोह का समापन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उज्ज्वल, स्वस्थ, समृद्ध एवं सुखमय जीवन की मंगलकामनाओं के साथ हुआ।

पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड अहमदाबाद द्वारा निःशुल्क शीतल जल सेवा का समापन एवं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान

पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड, जिला संघ अहमदाबाद के तत्वावधान में विगत एक माह से निरंतर संचालित की जा रही निःशुल्क शीतल जल सेवा का समापन दिनांक 31 मई, 2026 को किया गया। इस सेवा के माध्यम से स्काउट एवं गाइड सदस्यों द्वारा रेलवे यात्रियों को भीषण गर्मी के दौरान शीतल पेयजल उपलब्ध कराकर मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जल सेवा के समापन उपरांत पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड के सदस्यों ने साबरमती रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सदस्यों ने अपने हाथों में तंबाकू निषेध संबंधी संदेशों से युक्त तख्तियां लेकर रेल यात्रियों को तंबाकू एवं अन्य नशीले उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया तथा उन्हें तंबाकू सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

इसके पश्चात न्यू रेलवे कॉलोनी स्थित स्काउट डेन में आयोजित एक सम्मान समारोह में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, वटवा श्री अशोक कुमार द्वारा निःस्वार्थ भाव से जल सेवा में योगदान देने वाले जल सेवकों को प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर स्काउट परिवार के उन सदस्यों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने हाल ही में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एवं डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। फायर सेफ्टी ऑफिसर श्री गजेन्द्र बिहुला एवं एग्जामिनर श्री तेजस वाला ने प्रशिक्षित सदस्यों के दक्षता पदक प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर कर उन्हें प्रदान किए। साथ ही संस्था की ओर से उन्हें विशेष प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं स्काउट-गाइड सदस्यों ने समाज सेवा, आपदा प्रबंधन एवं जन-जागरूकता के ऐसे कार्यों को भविष्य में भी निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।